

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2016 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2016 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रभारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम उपस्थित हुए।

2. बैठक में उपस्थित प्रभारी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्देश दिया गया कि पटना नगर निगम से संबंधित लगभग 20 विधानमंडलीय प्रश्नों, जो दिनांक 30.11.2016 को ही सदन में पूछे जाने हैं, उन सभी का जबाब आज ही अप० 02:00 बजे तक अनिवार्य रूप से विभाग में उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :- नगर आयुक्त, पटना नगर निगम)

3. प्रशाखा पदाधिकारी-2, 3, 5, 10 एवं 11 को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित विधानमंडलीय प्रश्नों का प्रश्नोत्तर सामग्री नगर निकायों/संबंधित पदाधिकारियों से आज ही प्राप्त करके, ससमय जबाब तैयार करके संचिका में माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन हेतु उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी)

4. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि विकास भवन स्थित श्रम संसाधन विभाग का कार्यालय अन्यत्र स्थानांतरित हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ के सभी कमरे/हॉल वर्तमान में खाली हैं। निर्देश दिया गया कि श्रम संसाधन विभाग के खाली कमरे/हॉल को पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के बैठने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजा जाय एवं प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से मिलकर भी अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव)

5. पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑथोरिटी के गठन की संचिका विधि विभाग को भेजी गयी है। सहायक नगर निवेशक द्वारा बताया गया कि विधि विभाग द्वारा वह संचिका महाधिवक्ता को भेजी गयी है। सहायक नगर निवेशक को निर्देश दिया गया कि विधि विभाग से समन्वय करके संचिका का निष्पादन शीघ्र कराएंगे तथा पटना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑथोरिटी के कार्यालय की स्थापना एवं पद सृजन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करके संचिका में उपस्थापित करेंगे।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

6. पटना मास्टर प्लान के अंतर्गत जितने भी सड़कें हैं एवं इन सड़कों के सर्विस लेन, सिवरेज, बिजली, टेलीफोन लाईन आदि संरचना की मास्टर प्लान के तहत विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग के साथ समन्वय किया जाय एवं इस संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करायी जाय। बैठक हेतु PPT एक सप्ताह के अंदर तैयार करके संचिका में उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

7. पटना मास्टर प्लान को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दी जाय तथा पटना मास्टर प्लान के अंतर्गत Grid विकसित करायी जाय। ई०-म्युनिस्पिलिटी अंतर्गत Dash board विकसित करायी जाय। इस हेतु SPUR का सहयोग लिया जाय।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक एवं Team Leader, SPUR)

8. 01 जनवरी, 2017 से सभी नगर निगमों में मात्र ई०-म्युनिस्पिलिटी के माध्यम से Building Plan का कार्य किया जाना है। इस हेतु 01 जनवरी को दैनिक समाचार पत्रों में जनसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु प्रारूप तैयार कर संचिका में एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- Team Leader, SPUR)

9. Labour Cess संबंधी प्रावधान के संबंध में अन्य राज्यों में संवाहित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने हेतु सभी संबंधितों को पत्र भेजा जाय एवं जानकारी प्राप्त करके एक सप्ताह के अंदर संचिका में उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

10. Community Toilet एवं Public Toilet का detail Guideline तथा O&M तैयार करके सभी नगर निकायों को भेजा जाय। इस कार्य में श्री सामेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, श्री निखिल रंजन एवं श्रीमती शुभांजलि सक्सेना (SPMG) सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- श्री संजय दयाल, विशेष सचिव)

11. स्ट्रीट लाईट के संबंध में गाईडलाईन बनाने हेतु मुख्य अभियंता के स्तर पर एक कमेटी गठित की गयी थी, जिसके द्वारा अभी तक गाईडलाईन तैयार नहीं किया गया है। आज दिनांक 29.11.2016 को EESL के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में हुई चर्चा के आलोक गाईडलाईन तैयार किया जाय। यह कमेटी एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में detail Guideline तैयार करके अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालन :- मुख्य अभियंता, बुडा)

12. शेष बचे 40 शहरों का GIS Based Mapping का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। पटना मास्टर प्लान के RFP को शीघ्र अंतिम रूप देकर संचिका में एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :- Team Leader, SPUR एवं सहायक नगर निवेशक)

13. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर एक सप्ताह के अंदर अपलोड कराना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-5, 7 एवं आई०टी० मैनेजर)

14. विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री के 3 निश्चयों यथा नाली-गली योजना, पेयजल योजना एवं शौचालय निर्माण योजना तथा सबके लिए आवास योजना के अनुश्रवण हेतु जिले के सभी नोडल पदाधिकारी अपने संबद्ध नगर निकायों का स्थल भ्रमण करेंगे। नोडल पदाधिकारियों को स्थल भ्रमण के संबंध में तिथि निर्धारित करके विभाग द्वारा संसूचित कर दी गयी है। सभी पदाधिकारी निर्धारित तिथि के अनुरूप अपनी सुविधानुसार तिथि निर्धारित करके भ्रमण सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- सभी जिले के नोडल पदाधिकारी)

15. विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री के 3 निश्चयों यथा नाली-गली योजना, पेयजल योजना एवं शौचालय निर्माण योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु श्री अरविन्द कुमार झा (सहायक निदेशक), श्री सुरेश कुमार तिवारी (अधीक्षण अभियंता) एवं श्री सोमेश कुमार सिंह (कार्यपालक अभियंता) के दल द्वारा गाईडलाईन तैयार किया जाय, जिसमें यह स्पष्ट हो कि निकाय स्तर, जिला स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था किस प्रक्रियानुसार होगी। यह दल एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से गाईडलाईन प्रारूप तैयार करके संचिका में उपस्थापित करना सुनिश्चित करेगी।

(अनुपालन:- श्री अरविन्द कुमार झा (स०नि०), श्री सुरेश कुमार तिवारी (अधी०अभि०) एवं श्री सोमेश कुमार सिंह (कार्य० अभि०))

16. सभी जिले के नोडल पदाधिकारी संबद्ध जिले के नगर निकायों में, जहाँ मुख्यमंत्री के निश्चयों का कार्यान्वयन अच्छा हो रहा हो, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री से योजना का उद्घाटन/शिलान्यास कराया जा सके।

(अनुपालन :- सभी जिले के नोडल पदाधिकारी)

17. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अभी हाल ही में भू-संपदा आरक्षण नियमावली लागू की गयी है। आरक्षण नियमावली के आलोक में आवास आवंटन के लिए Action Plan तैयार करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को निर्देश भेजा जाय।

(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन-सह-संयुक्त सचिव)

18. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का O&M Policy बनाने का निर्देश पूर्व में बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया था, जो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। पॉलिसी तैयार करने हेतु श्री सतीश चंद्र अग्रवाल (SPUR) बिहार राज्य जल पर्षद से अग्रेत्तर समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- Team Leader, SPUR)

19. मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा जाय कि वे जिले में पदस्थापित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक कनीय अभियंता को उस क्षेत्र के प्रत्येक नगर निकायों में पेयजल योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए अल्पकालिक रूप से संबद्ध करेंगे ताकि योजना के कार्यान्वयन में तीव्रता आ सके तथा मुख्य सचिव के उक्त निर्देश को सुनिश्चित कराने हेतु प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को भी अनुरोध पत्र भेजा जाय। पत्र प्रारूप तैयार कर मुख्य सचिव के अनुमोदन हेतु संचिका में आज ही प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

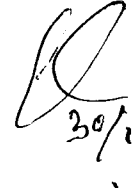
(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-1)

20. नगर निकायों/डूडा/बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद को विभाग द्वारा आवंटित की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रतिदिन अप० 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश पिछली बैठक में दिया गया था, लेकिन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। निर्देश दिया गया कि दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-7)

21. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

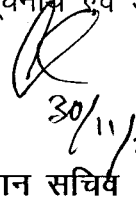

30/11/2016

(चैतन्य प्रसाद),

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8904 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 30/11/16

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/Team Leader, SPUR/SPMG कोषांग/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/11/2016
प्रधान सचिव

➤ **प्रशाखा-01 :-**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, विहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ **प्रशाखा-02 :-**

1. गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जयन्ती की तैयारी हेतु प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

2. **सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-**

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

3. **स्ट्रीट लाईट :-**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

4. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्यवाही की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

5. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांशों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।

4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डीपीआर बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➤ प्रशाखा-04 :-

1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके, प्रस्ताव गठित किया जाय।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

• NULM से संबंधित कार्य :-

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➤ प्रशाखा-05 :-

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।

2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।

5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

6. नगरीय प्रशासन :-

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➤ प्रशाखा-6 :-

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➤ प्रशाखा-07 :-

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➤ प्रशाखा-8 :-

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➤ प्रशाखा-9 :-

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक प्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. TCPO कार्यालय का सुदृढीकरण।

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :-**

- (i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
- (ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।